NT>

Title: Need to write-off agricultural loans of Rs.50,000 of farmers in Jammu and Kashmir.

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : सभापति जी, पिछली सरकार में श्री देवेगौडा जी ने जम्मू-कश्मीर के लिए एक पैकेज अनाउंस किया था। वह पैकेज इसलिए अनाउंस करना पड़ा कि वहां पर इनसर्जेन्सी थी और इनसर्जेन्सी में लोगों ने जो भी कर्जे लिये थे, वह किसी भी काम में नहीं लगा सके और वह वापस नहीं हो पा रहा था। उन्होंने ५०,००० रुपये तक के सबके कर्जे माफ कर दिये थे, परंतु मैं समझता हूं कि कहीं पर भूल हुई है। उसमें जो ऐग्रीकल्चर लोन किसानों ने लिये हैं, उसको इस दायरे में नहीं लाया जा रहा है। आप भी जानते हैं कि कितने किसान इस बात के लिए आत्महत्या कर चुके हैं कि वे कर्जे वापस नहीं कर सके। ५०,००० रुपये तक के जो कर्जे माफ हुए हैं वह शिकारा चलाने वालों के माफ हुए हैं, होटल चलाने वालों के माफ हुए हैं लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि किसान का कर्जा क्यों माफ नहीं हो रहा है।

मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में किसानों के ऐग्रीकल्चरल लोन्स जो ५०,००० रुपये तक के हैं, उनको तुरंत माफ किया जाए।